

Original Article

नवजात शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर को कम करने में टीकाकरण की भूमिका

किरण कुमारी

शोधार्थी, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

Email- kiranchy1989@gmail.com

Manuscript ID:

सारांश

JRD -2025-170751

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 71

Pp. 266-269

July 2025

Submitted: 20 June. 2025

Revised: 30 June. 2025

Accepted: 15 July. 2025

Published: 31 July. 2025

भारत नवजात कार्य योजना के माध्यम से अजन्मे नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। मिशन इंद्रधनुष योजना के द्वारा 2 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सात तरह की बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा से बचाव के लिए इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गर्भवती महिलाओं को भी टिटनस से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 साल में 2.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 70 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। साथ ही, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को रोटावायरस और डायरिया से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके लगाए गए। महिलाओं और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और मृत्यु दर को कम करने के लिए उनको सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में नियमित आहार के रूप में मिलना चाहिए। अक्सर घरों में पुरुषों के आहार की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है और महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला तैयार करने में सहयोगी होती है। जिसमें मातृ व शिशु स्वास्थ्य की भूमिका सबसे अहम होती है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व जांच, प्रसव उपरांत देखभाल, नियमित टीकाकरण, घर में नवजात शिशु देखभाल, कमजोर नवजात देखभाल एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जैसे कई अभियान हैं, जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। भारत के असम राज्य में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्म पर यह आंकड़ा सबसे कम है। यूनेस्को के अनुसार, भारत की मातृ मृत्यु दर में 2000 से 2020 तक 6.36% की गिरावट हुई है, जो वैश्विक गिरावट की दर से तीन गुना अधिक है। प्रसव से लेकर शिशु देखभाल के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा करना पुरुषों की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि पुरुष को सुरक्षित मातृत्व के विषय में जागरूक एवं संवेदनशील होना चाहिए। पुरुषों की जागरूकता मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में प्रभावी साबित हो सकता है।

मुख्य शब्द- मातृ, शिशु, मृत्यु, इंद्रधनुष, स्वास्थ्य

परिचय

टीकाकरण से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। टीकाकरण से संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है और समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। बच्चों के जीवित रहने की कुंजी टीकाकरण बच्चों के जीवन और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे किफायती तरीकों में से एक है। भारत का टीकाकरण अभियान यूआईपी दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। हर साल लगभग 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं और 3 करोड़ 40 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए देश भर में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकाकरण अभियान चलाये जाते हैं।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdrv.org/>

DOI:10.5281/zenodo.16931372



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

किरण कुमारी, शोधार्थी, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:

किरण कुमारी. (2025). नवजात शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर को कम करने में टीकाकरण की भूमिका. *Journal of Research & Development*, 17(7), 266–269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16931372>

विगत दो दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने के दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन का सर्टिफिकेट मिला। देश भर में खसरा-रूबेला, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और रोटावायरस वैक्सीन सहित नए टीके लॉन्च किये गये और बांटे गए। इसके बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं। 2022 में 1 करोड़ 43 लाख शिशुओं को वैश्विक स्तर पर पहला डीपीटी टीका नहीं मिला, जो टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दिखाता है। इसके अलावा 6.2 मिलियन को थोड़ी-थोड़ी वैक्सीन दी गई। इस प्रगति के बावजूद भी भारत में शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता में संक्रामक बीमारियों की उच्च भागीदारी है। भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपने पांचवा जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से अधिकांश को शिशु स्तनपान टीकाकरण एवं उपचार देकर बचाया जा सकता है। भारत सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने और समुदायों को उन बीमारियों से बचाने के लिए समर्पित है जिन्हें टीके रोक सकते हैं। एनएफएचएस-5, 2019-21 के अनुसार, देश का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 76.1 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि हर चार में से एक बच्चा आवश्यक टीकों से वंचित है। WUENIC डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ एस्टीमेट्स नेशनल इम्प्यूनाइजेशन कवरेज के अनुसार भारत ने 2021 की बजाय 2022 में जीरो डोज को 27 लाख से घटाकर 11 लाख कर दिया है। इसके अलावा जीवन रक्षक टीकाकरण में 16 लाख बच्चों को कवर किया गया है। भारत टीकाकरण एजेंडा 2030 तक जीरो-डोज के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोग्रेसिव कदम उठा रहा है। हालांकि, लाखों बच्चे अभी भी टीकाकरण के इंतजार में हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में टीकाकरण की दर अलग-अलग है। जीरो डोज के 63% शिशुओं संख्या बड़े राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। कुल मिलाकर यह जन्म समूह का 55% बनता है। जीरो डोज वाले शिशुओं का उच्च अनुपास मेघालय में 17.8%, नागालैंड में 15.8%, मिजोरम में 14.5% और अरुणाचल प्रदेश में 13.4% है। जीरो डोज वाले शिशुओं की संख्या में कमी का श्रेय मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को जाता है। इसका मकसद चुनिंदा जिलों और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के अंतर को कम करना था। कोविड-19 के प्रभावों से उभरने के लिए फरवरी 2022 में 0.4 IMI अभियान चलाया गया। इसमें टीकाकरण रहित और कम डोज के टीकाकरण वाले बच्चों को वैक्सीन दी गई। साथ ही ज्यादा प्रकोप वाले राज्यों की पहचान कर रोडमैप के जरिए खसरा और रूबेला कैचअप अभियान चलाया गया। वर्ष 2023 में राष्ट्रव्यापी कवरेज सुधार के लिए अगस्त, सितंबर-अक्टूबर में IMI 5.0 अभियान आयोजित किया गया था। इसमें दो से पांच साल के बच्चों तक टीकाकरण पहुंच बढ़ाई गई थी। अभियान में विशेष रूप से ऐसे बच्चे शामिल किये गये, जिनकी एमआर खुराक छूट गई हो। इस तरह देश को एमआर उन्मूलन के लिए तैयार किया गया। मातृ टीकाकरण माताओं, विकासशील भ्रूण और छोटे शिशुओं को उनके जीवन के विशेष रूप से संवेदनशील समय के दौरान सुरक्षित रखने के लिए एक आशाजनक रणनीति है - विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां महिलाओं और उनके बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर अधिक है। गर्भावस्था के दौरान, टीके माँ से एंटीबॉडी को प्लेसेंटा में जाने देते हैं, जिससे माताओं और उनके शिशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है।

भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांवों में रहती है, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की 2013 के रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, डाक्टर में से 33% डॉक्टर ही वहां काम करते हैं। इसी वजह से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है तथा वहां मातृ - शिशु मृत्यु दर अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने बच्चों एवं गर्भवती माता के लिए टीकाकरण का मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई है। इसके अंतर्गत सरकार आवश्यक सभी टीके सभी को लगवाने का प्रयास कर रही है। सभी गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व व प्रसव सब के बाद सेवाएं प्रदान करना तथा सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2010 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक वेब आधारित प्रणाली लागू की। जिसे मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह सभी गर्भवती महिलाओं और पांच वर्ष तक के बच्चों को के व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करता है। मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि सभी गर्भवती महिलाओं को पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण और प्रसव के बाद देखभाल सेवाएं प्राप्त हो और सभी बच्चों को टीकाकरण सेवा की पूरी श्रृंखला प्राप्त हो। दुनिया भर में समय पूर्व प्रसव नवजात बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है। भारत में साल भर में पैदा होने वाले 27 मिलियन बच्चों में से 3.6 मिलियन बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। इसमें से 3 लाख से अधिक समय पूर्व जन्म होने वाले बच्चे विभिन्न जटिलताओं के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। इस मिशन में उन बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें टीके लगाए ही नहीं गए या फिर आधे अधूरे लगे हैं। इस मिशन के तहत बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी से पूरी तरह प्रतिरक्षित करना तथा गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगाने का योजना है। देश के चुनिंदा राज्यों और जिलों में जापानी एसेफेलिडिटिस और हीमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी के खिलाफ भी टीकाकरण किया जाएगा। भारत में हर साल 28 दिन से कम उम्र के लगभग 7.5 लाख नवजात बच्चे अपरिपक्वता और दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए सरकार ने सितंबर 2014 से भारत नवजात कार्य योजना शुरू की है। भारत में प्रति 1000 जन्म में नवजात शिशु की मृत्यु दर 28 है। नवजात कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक इस मृत्यु दर को 10 से कम करने का है। साथ ही, इस योजना के तहत गर्भावस्था प्रसव के समय और उसके बाद महिलाओं की देखभाल के अलावा किशोरियों के स्वास्थ्य पर

भी ध्यान देना है। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर जैसे संवेदनशील विषयों को कम करने के लिए पूर्व में प्रयास करने के बावजूद भी हम वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जो की अपेक्षित है। इसीलिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इस ओर कोई न छोड़ने के उद्देश्य से 1 जून 2011 को जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है और जच्चा- बच्चा की सुरक्षा है। इसके लिए सेवा प्रबंधकों और गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी संपर्क बनाने, प्रसव कराने के लिए महिलाओं के साथ प्रसव केंद्रों पर जाने और उनकी मदद करने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। इसे संक्षेप में, आशा का नाम दिया गया है। कुपोषण से भी बहुत बच्चे मर जाते हैं। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में पांच साल से कम उम्र के लगभग दस लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। सरकार द्वारा मिड डे मील की योजना सभी स्कूलों में इसी उद्देश्य शुरू की गई है कि देश का सभी बच्चा को कुपोषण से मुक्त हो सके। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अहम उद्देश्य है, इसीलिए जननी सुरक्षा योजना के अलावा टीकाकरण योजना पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सक्षम आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित टीकाकरण सबसे प्रभावी लोक स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में टीका निवारणीय रोगों के कारण मृत्यु दर को कम करना है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम, प्रयुक्त टीकों की मात्रा, लाभार्थियों की संख्या, आयोजित टीकाकरण सत्रों की संख्या और कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलताएं शून्य है, ऐसा नहीं है। चूंकि भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक दबाव है। परंतु, इसके बावजूद मातृ - शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। कुछ आंकड़ों के अनुसार 2005 में शिशु मृत्यु दर एक हजार शिशुओं में से 58 थी। जो 2012 में 42 दर्ज की गई। मातृ मृत्यु दर 2001 - 2003 में 1 लाख में 301 थी। जो 2007 -2009 में 212 तक आ गई। इसको कम करने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं जननी सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों में लागत की दृष्टि से सबसे किफायती है और मृत्यु दर तथा टीकों के निवारण योग्य बीमारियों की संख्या कम करने में काफी हद तक मददगार है। दुनिया भर से चेचक का उन्मूलन और भारत से पोलियो, याँज तथा माता एवं नवजात शिशु संबंधित टिटनेस की समाप्ति जैसी सफलताएं संचारी रोग के अभिशाप से मुक्ति में टीकाकरण की भूमिका को दर्शाती है। यूआईपी 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया था। 1997 से टीकाकरण गतिविधियों राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है और 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रही है। यूआईपी के अंतर्गत भारत सरकार समूचे देश में निवारण योग्य 11 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डिमागी बुखार और हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी से होने वाले निमोनिया, बचपन में होने वाले गंभीर क्षयरोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा तथा चुने हुए राज्यों में रूबेला और रोटावायरस, अतिसार और स्थानीय जिलों में जैपनीज एंसेफलाइटिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान संचालित करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष 2.67 करोड़ से अधिक नवजात शिशु और 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाता है। एनएचएम का पहला ध्यान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर था। जे एस वाई और आशा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है और बड़ी तादाद में गर्भवती स्त्रियां शारीरिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंची। नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से आरंभ की गई भारत नवजात का योजना के तहत जिला स्तर पर विशेष नवजात देखभाल इकाईयां और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नवजात स्थिरीकरण इकाईयां स्थापित की गई हैं। एनएचएम के तहत मिशन परिवार कल्याण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा कार्यक्रम की गतिविधियों पर लगातार ध्यान बना हुआ है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का लक्ष्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जननी एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। सरकार ने प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आरंभ किया है। एनएचएम का प्रमुख लक्ष्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना और नवजात मृत्यु दर को 2018 तक घटकर 28 कर देना था। मातृ मृत्यु दर 2011 में सर 167 थी। 1990 में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 126 थी। जो कि 2014 में केवल 39 हो गई। किसी भी देश के विकास के संदर्भ के लिए पहली प्राथमिकता जन - स्वास्थ्य को दी जानी चाहिए। क्योंकि, जान है तो जहान है, और स्वास्थ्य है तो, ही जान है। जन स्वास्थ्य के मामले में महिला और बाल स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि एक तो यह दोनों समूह मिलकर देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। साथ ही, बच्चे देश के कर्णधार होते हैं और महिलाएं उन कर्णधारों को जन्म देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 46 है, जबकि कुल शिशु मृत्यु दर 41 है। इसके पूर्व के सर्वे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-2006) में देश की कुल शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार थी। शिशु एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट के अतिरिक्त हमारे देश से मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है। सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2011-13 के रिपोर्ट के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 167 थी। यह संख्या वर्ष 2004-06 में 254 थी। इस प्रकार पिछले एक दशक में मातृ मृत्यु दर में कुल 87 अंकों की कमी आई। सर्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के तीन चरणों में अगस्त 2016 तक सरकार को कुल 5.27 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 54.5 लाख बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण एवं 55.4 लाख गर्भवती स्त्रियों का टिटनस टाक्साइड टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। इससे बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, वे बीमारियों से बचे रहेंगे और उनके जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत सितंबर 2014 से शुरू की गई। इसका

उद्देश्य 2030 तक शिशु मृत्यु दर और मृत शिशु जन्म दर को कम करना है। किलकारी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत गर्भावस्था, प्रसव तथा देखभाल के बारे में साप्ताहिक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य की गई है। बाल मृत्यु दर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह महसूस किया गया है कि प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर एक दूसरे को से अलग विचार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, ये विभिन्न आयु वर्ग की हमारी जनसंख्या के स्वास्थ्य के स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक किशोरी के स्वास्थ्य का असर गर्भावस्था पर पड़ता है। जबकि गर्भवती माता के स्वास्थ्य से नवजात शिशु और बच्चे का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए माता और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर आवश्यक उपाय किया जाने चाहिए। प्राथमिक यानी घर से लेकर सामुदायिक स्तर तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसके लिए इंतजाम होने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल में तत्काल चिकित्सा देखभाल, नवजात शिशु की रोजमर्रा की देखभाल, बीमार शिशु की देखभाल, बाल पोषाहार, बचपन की आम बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और नवजात शिशुओं की आम बीमारियों का इलाज शामिल है। भारत नवजात मिशन का लक्ष्य नवजात व अजन्मे में शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना है। वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 7.47 लाख नवजात शिशु मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अनुमान है कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद 2030 तक ये संख्या 2.28 लाख /वर्ष से कम हो जाएगी।

निष्कर्ष:-

मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। इसके तहत लोगों को घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी जा रही है। प्रसव के विषय में जानकारी होने पर घर में तैयारियां शुरू होती हैं, उसी प्रकार घर के सदस्यों को उसके प्रसव कराने के विषय में भी कार्य योजना बनानी चाहिए और उसकी के अनुसार महिला की जांच से लेकर प्रसव तक की तैयारी करनी चाहिए। ताकि प्रसव के दौरान उसको सारी सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के लिए योजना चल रही है। इसका विधिवत क्रियान्वयन और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वच्छता में सुधार, स्वच्छ पेय जल तक पहुंच, संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से मातृ-शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को कम करने में सहायता मिल सकती है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा सभी प्रसव आयु वर्ग की महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए रोकथाम के उपाय गर्भधारण से पहले शुरू किए जाने चाहिए और प्रसवोत्तर अवधि तक जारी रहने चाहिए। दार्द्री की देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच से मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु और मृत जन्म में से 60% से अधिक को रोका जा सकता है - जिससे 2035 तक प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों के जीवन को बचाया जा सकेगा। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गर्भवती और बच्चों का नियमित टीकाकरण भी जरूरी है। नियमित टीकाकरण के सफल संचालन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। प्रशिक्षण का उद्देश्य एएनएम को नियमित टीकाकरण के फायदे के बारे में अवगत कराना, टीके के रख-रखाव के तरीके बताना और कितने समय पर कौन सा टीका लगाया जाये, इस संबंध में सही-सही जानकारी देना है।

संदर्भ सूची-

1. सक्सेना ऋषभ कृष्ण ,(2015)कुरुक्षेत्र पत्रिका,जुलाई ,पृष्ठ संख्या-5-6
2. तिवारी सुधीर ,(2015),कुरुक्षेत्र पत्रिका ,जुलाई ,पृष्ठ संख्या-12
3. तिवारी सुधीर ,(2015) , कुरुक्षेत्र पत्रिका ,जुलाई , पृष्ठ संख्या-14-15
4. सास्वत डाॅ ऋतु ,(2015),कुरुक्षेत्र पत्रिका, जुलाई , पृष्ठ संख्या-31-32
5. नड्डा जे० पी ,(2017),कुरुक्षेत्र पत्रिका , जुलाई ,पृष्ठ संख्या-5
6. श्रीवास्तव बी० ,(2017)कुरुक्षेत्र पत्रिका ,जुलाई ,पृष्ठ संख्या-9-10
7. नकवी हेना ,(2017)कुरुक्षेत्र पत्रिका ,जुलाई ,पृष्ठ संख्या-28-29
8. शर्मा डाॅ० ज्योति ,(2019),कुरुक्षेत्र पत्रिका ,सितम्बर ,पृष्ठ संख्या-37
9. पासी डाॅ० संतोष जैन एवं जैन आकांक्षा , (2019),कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च,पृष्ठ संख्या-25
10. <https://immunizationevidence.org>
11. <https://pin.gov.in>
12. <https://www.Unicef.org/india>
13. <https://hi.Wikipedia.org/wiki>